

रक्षाबंधन वक्त की मार पर भारी प्यार

राखा पक पर मन का उमड़-धुमड़ पहले की ही तरह है, लेकिन बाहर एक 'खाँफ' का माहौल है। सभी भाई-बहन यही दुआ कर रहे हैं कि यह खोफाक वक्त जल्दी टले और हालात सामान्य हों। कभी दूरी के कारण डाक व्यवस्था के जरिये प्यार के संदेश भेजे जाते थे तो आज कोरोना जैसी महामारी ने दूरी को जरूरी बना दिया है। समय की रफतार के साथ हर त्योहार के तौर-तरीकों में बेशक बदलाव आया हो, लेकिन यादों के झगड़ों से झांकें तो सबको वे भावुक पल याद आते हैं जब इंतजार होता था अपने भाई या बहन का।

रेलवे स्टेशन पर गाड़ियां आ रही थीं। जा रही थीं। आठ-नौ साल की लटका था। उस पर राखा के गान बज रहे थे। वह स्टेशन पर बहुत देर से खड़ी थी, लेकिन गाड़ी आ ही नहीं रही थी। फिर अचानक अखबार बेचने वाले शर्मा चाचा जी ने उसे बताया कि अब जो गाड़ी आएगी, वह दिल्ली से ही आएगी। बच्ची खुश हो उठी। उसे डाउन हुआ सिग्नल भी दिखने लगा। जल्दी ही एक काला गोला नजर आया। फिर इंजन नजर आने लगा। गाड़ी दौड़ी चली आ रही थी। गाड़ी प्लेटफर्म पर शोर करती रुकी तो बच्ची इधर से उधर दौड़ने लगी। हर डिब्बे और दरवाजे के पास जाकर वह देखने लगी। आखिर के ब्रेक से लेकर इंजन तक दौड़ी कि अचानक गाड़ी ने

बच्चा बड़ा आशाभरी नजरो से हर आती गाड़ी को देख रही थी, लेकिन जिस गाड़ी का उसे इंतजार था, उसका दूर तक पता नहीं था। जब वह रेलवे स्टेशन के लिए घर से निकली थी, तब पास से एक साइकिल सवार निकला था, उसकी साइकिल पर एक ट्रांजिस्टर सोटी बजा दो और डिब्बे खिसकने लगे और रफ्तार पकड़ ली। सबेरे से बच्ची को जिनका इंतजार था, वह बड़े भाई तो आए ही नहीं। रातभर उसे नींद भी नहीं आई थी। बड़े भाई दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ते थे। उससे ऊनीस साल बड़े थे। वह अपने माता-पिता के साथ

की जरूरत थी

बात शामिल नहीं होगा, तो किसी आरक्षन में हम न ता चितन कर सकते हैं, न प्रयोग कर सकते हैं। इस नाते नयी शिक्षा नीति की बहुत आवश्यकता थी। इस शिक्षा नीति के चार कंपोनेट हैं। पहला विद्यालयी शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा और तीसरा शोध का है। चौथा कंपोनेट नियामक से जुड़ा हुआ है कि देश की शिक्षा किस तरह संचालित होगी। विद्यालयी शिक्षा को लेकर बहुत दूरगमी कदम उठाया गया है। इसमें तीन वर्ष की उम्र से लेकर 18 वर्ष की उम्र यानी बारहवीं तक बच्चे को विद्यालयी शिक्षा के साथ जोड़कर रखने और शिक्षा को समावेशी बनाने का प्रावधान है। अंगनबाड़ी को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने की बात है। यहां नीति-निर्माताओं से केवल एक आग्रह है कि छोटी उम्र के बच्चों पर बस्ते का बोझ न लादा जाये। उनको आरंभिक दिनों में खेल-कूद या मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाये। मातृभाषा में शिक्षा देने का विचार भी उल्लेखनीय है। गांधीजी भी मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करते थे। एक तरह से देखा जाये तो इस नयी शिक्षा नीति का प्रारूप गांधीजी की शिक्षा नीति के बहुत नजदीक है। इसके अलावा, स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने और बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात भी शिक्षा नीति में शामिल है, जो स्वागतयोग्य है। दूसरा कंपोनेट उच्च शिक्षा का है। चार वर्षीय यूजी प्रोग्राम की अब जो संरचना आ रही है, उसकी वैश्विक परिदृश्य के साथ एकरूपता है, पहले की उच्च शिक्षा में वैश्विक परिदृश्य के साथ एकरूपता की कमी थी। चार वर्षीय

यूजी प्रोग्राम में अगर कोई विद्यार्थी किन्हीं कारणों से एक वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है तो उसका वर्ष बर्बाद नहीं होगा, बल्कि उसका क्रेडिट जमा हो जायेगा और उसको सर्टिफिकेट मिल जायेगा। दो वर्ष के बाद यदि पढ़ाई छूट जाती है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। तीन वर्ष पर डिग्री मिल जायेगी। उसका क्रेडिट आगे चलकर चतुर्थ वर्ष और हायर स्टडीज में भी लागू हो सकता है। ग्रॉस एनरालमेंट रेशेयो यानी जीईआर को 2035 तक 50 प्रतिशत तक ले जाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, जो बहुत बड़ा कदम है। अगर हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं तो यह देश की शिक्षा के लिए, समाज के लिए बहुत बेहतर होनेवाला है। बहुत प्रयासों के बावजूद हमारा जीईआर अभी 26 प्रतिशत के करीब ही पहुंचा है। इतना ही नहीं, अब कोई भी विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार एक क्रेडिट कोर्स जैसे मानविकी, साहित्य या स्किल ले सकता है। इस लिहाज से उच्च शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन आने वाला है। विज्ञान के विद्यार्थी पहले समाज, साहित्य आदि के बारे में पढ़ ही नहीं पाते थे। नयी शिक्षा नीति अब विद्यार्थियों को उसके सीमित दायरे से निकालकर विस्तृत दायरा देने जा रही है। इस तरह अब विद्यार्थियों के विकास, मानसिक विकास, व्यक्तिगत प्रयासों के लिए संभावनाएं कहीं ज्यादा हैं। और जब ज्यादा संभावनाओं वाला क्षेत्र होता है तो उसका लाभ राष्ट्र और समाज के साथ उद्घासित को भी मिलता है। रोजगार की दृष्टि से भी यह नीति बहुत फलदायी रहने वाली है। शोध आधारित विश्वविद्यालय का भी नयी नीति में प्रावधान है, जिससे देश में पब्लिकेशन, रिसर्च की संस्कृति को और मजबूती मिलेगी। विश्व के जितने भी विश्वविद्यालय अच्छा करते हैं उनका रिसर्च कंपोनेंट, रिसर्च आउटपुट और पब्लिकेशन बहुत महत्व रखता है। आज भी जिस प्रोफेसर का साइटेशन जितना अच्छा होता है वह उतना ही अच्छा एकेडमिशन माना जाता है। चौथा कंपोनेंट गवर्नेंस का है। नये प्रावधान के तहत तमाम प्रशासकीय व्यवस्थाओं को खत्म करके उसे एक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जायेगा, जो सराहनीय है। इस शिक्षा नीति में शिक्षा के भारतीयकरण की बात भी कही गयी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी अवधारणा है। हमारे यहां भारतीय दर्शन पढ़ाया ही नहीं जाता, विदेशी विचारक पढ़ाये जाते हैं। हमारे ऋषियों-मनीषियों ने हजारों-हजार वर्ष पहले दर्शन दिया। हमारे आधुनिक शिक्षा जगत के सबसे बड़े मनीषियों डॉ राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, गांधीजी या दीनदयालजी ने भारतीय शिक्षा के बारे में क्या सोचा उसे कोई नहीं बताता। शिक्षा के भारतीयकरण से औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और भारत, भारतीयता और भारत के प्रति विद्यार्थियों में स्वाभाविक तौर पर प्रेम पैदा होगा। नयी नीति में पाली, प्राकृत, संस्कृत भाषा की पढ़ाई और शोध समेत लम्पाय द्वारा चक्री भाषाओं के संग्रहण की बात भी की गयी है।

रहता था। भाई रक्षाबद्धन, हालांकि दिवाली पर जरूर आते थे। बाकी परिवार के लोग-चाचा, ताऊ उनके बच्चे भी इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन इस बार गांव से कोई नहीं आया। भाई ने कहा था कि वह आएंगे, लेकिन वह भी नहीं आए। बच्ची जोर-जोर से रोती घर पहुँची। मां ने उसे समझाया कि हो सकता है गाड़ी निकल गई हो। शाम की गाड़ी से आते हों। लेकिन शाम की गाड़ी भी बिना भाई को लाए ही चली गयी। बच्ची रुठ गई। वह नाराज तो थी ही, इस बात से दुखी भी थी कि भाई के लिये उसने पिता जी से खास रेशमी राखी मंगवाई थी। अब वह राखी किसको बांधेगी। तब पिता जी ने उसे बताया कि भाई की छिड़ी आ चुकी है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश की तरह राखी की छुट्टी नहीं होती है, इसलिए वह नहीं आएगी। उस दिन उनका कालेज खुला है। नयी नौकरी है, इसलिए छुट्टी भी नहीं ले सकते। बच्ची नाराज होती हुई बोली-तो पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए कि तू रोती और

रात हा जाता। एता का बात सुनकर बच्ची जोर-जोर से रोने लगी। उन्होंने उसे मनाया, लेकिन वह नहीं मानी। वह बड़े भाई से बहुत नाराज थी। बच्ची उदास थी तभी ऐन रक्षा बंधन के दिन भाई के पक्के दोस्त वीरेंद्र भाई साहब आ पहुंचे थे। वह उसके लिए रक्षा बंधन के उपहार के रूप में मिट्टी के बने दो चमकते हुए काले घोड़े लाए थे। उन्होंने उससे राखी बंधवाई, सिर पर हाथ फेरा, पांव छुए, पैसे भी दिए, मां के आग्रह पर खाना भी खाया। बच्ची को मेरी प्यारी बहन कहकर दुलारा। कहा कि अब हर साल वह उससे राखी बंधवाने आया करेगे।

कुछ दिन बाद डाक से एक बड़ा लिप्पफ्फ आया। भाई ने दिल्ली से भेजा था। उसमें उसके लिए नयी दो प्रॅक, प्लास्टिक का एक मोर, बिस्कुट और टॉफी के डिब्बे थे। भाई ने विशेष तौर से उसके लिए चिढ़ी भी लिखी थी और कहा था कि जैसे ही छुट्टी मिलेगी वह आएंगे और अपनी प्यारी गुड़िया को मना

लगा। उह पता ह कि उनका छाटा बहन कभी उनसे नाराज नहीं हो सकती। असल में राखी के पर्व की यह भावुकता हर दौर में रही है, लेकिन अब तो दौर ही अजीब हो गया है। उन दिनों इस बच्ची की तरह बहुत सी बच्चियां भाइयों का इंतजार करती थीं। कुछ विवाहित स्त्रियां जो किसी कारण से मायके नहीं जा पाती थीं, उन्हें अपने-अपने भाइयों के आने का इंतजार रहता था। जिन लड़कियों के भाई या बहन नहीं होती थीं वे अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लड़के, लड़कियों को भाई-बहन बना लेती थीं। यह रिश्ता जीवन भर चलता था। आज स्त्री विमर्श रक्षा बंधन में जुड़े रक्षा शब्द से बहुत नाक-भौं सिकोड़ा है। वे कहते हैं कि इस शब्द में ही यह छिपा है कि लड़कियां कमजोर होती हैं। वे अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकतीं। हालांकि आज भी समाज में महिला सुरक्षा बड़ा मसला है। लड़कियां इन दिनों भी रात-बिरात बिना किस पुरुष के साथ बाहर नहा जानकारी बहन के पिल्लमों ने नहीं है। बहना प्यार बांधा बंधन को अकसर रे अवसर पर रक्षा बंधन पूरी, आलू संबंधियां विकंडों पर गेंद कुल्हों को रहता था। यह एक अच्छी हो, थी। मशहूर सचदेव बूद्धाबाबड़ी का जिक्र गम्भीर रूप कशमीर वंश दाखिल शब्द बहुत उदासीन साहब अमारे आए। उन सचदेव रो

ल सकता। भाई आर आपसी प्यार को हमारी भी खूब सेलिब्रेट किया ने भाई की कलाई से है या भैया मेरे राखी के निभाना- गाने आज भी डियो पर रक्षाबंधन के दूसरे सुने जाते हैं। घर में के अवसर पर खीर, की सब्जी, रायता और प्रेशेष रूप से बनती थीं, हूँ बोए जाते थे। जिनके कानों में लगाया जाता एक तरह से नयी फसल इसकी चाहत भी होती हूँ कथाकार पदमा ने अपनी आत्मकथा में एक दिलचस्प प्रसंग किया है। बचपन में वह प से बीमार हुई थीं। के एक अस्पताल में रक्षाबंधन के दिन अस थीं। तभी डॉक्टर पने मरीजों को देखने होने देखा कि पदमा रही हैं। कारण पूछा तो बता दिया एक आज रक्षाबंधन ह। यहां किसे राखी बाधे। डॉक्टर साहब ने अपनी कलाई आगे कर दी। और यह रिश्ता तब तक चला जब तक डॉक्टर साहब इस दुनिया में रहे। यह डॉक्टर साहब मुसलमान थे। बदले वक्त ने चाहे इस त्योहार के रूप को बदल दिया हो, जीवन में अनेक पकवानों, तरह-तरह के महगे उपहारों का प्रवेश हो गया हो, मगर बहन की नजरों में भाई और भाई की नजरों में बहन की ज़रूरत कम नहीं हुई है। बचपन में जो राखियां मिलती थीं, उनमें बहुत सी राखियों में सफेद प्लास्टिक के हनुमान जी, शिव जी गणेश जी, राम परिवार, मोर, गाय, कमल, गुलाब के पूर्ण आदि चिपके रहते थे। बच्चों में इन्हें बटोरने की होड़ लगी होती थी। बाकी राखियों में चिपके गोटे, चमकीली पत्रियां गुड़ियों के घर सजाने के काम आती थीं। रंग-बिरंगी रेशमी लच्छियां लाकर, उन्हें मोड़कर कैंची से काटकर, दो-चार टांके लगाकर, घर में भी सुंदर राखिया बनाइ जाता था। आज अनेक किस्म की डिजाइनर राखियां मौजूद हैं। बेशक कोरोना काल का असर राखी के कारोबार पर पड़ा हो, लेकिन भावनाएं अपनी जगह पर हैं। यूं तो सावन का महीना ही जैसे उत्सवों से जुड़ा था। रिमझिम बारिश, ऊँचे, मजबूत तनों वाले पेड़ों पर पड़े झूले, सावन के सोमवार, शिवजी की विशेष पूजा, फिर रक्षा बंधन। जैसे कि हमारे खेत, नदी तालाब बारिश के होने का जश्न मनाते थे और बारिश अच्छी हो तो कृषि और फसलों के अच्छे होने की उम्मीद बंधती थी, इसलिए सावन, भादों और बारिश से जुड़े महीनों का खासा महत्व था। उत्तर प्रदेश के बहुत से इलाकों में एक नियम सा था कि रक्षाबंधन के दिन विवाहित बहनें भाइयों को राखी बांधने अपने मायके जाती थीं और भैया दूज के दिन भाई टीका करने विवाहित बहन के घर जाते थे। इस अवसर पर कहानियां भी कही जाती थीं।

प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे सम्मान विजेता तथा देश के जाने माने पत्रकार व टी बी एंकर रवीश कुमार लिखिन् यहाँमें प्रभु आपो सलाह देते हैं ? आखिर इसका क्या कारण है, इस सवाल का जवाब आज के मुख्य धारा के टी बी चैनल्स को देवरकुम रवीश भारतीय जैसे अनेक गंभीर पत्रकारों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक इसके विपरीत किसी भी कार्यक्रम के इन्हें कार्यक्रम संचालित व प्रसारित करते हैं, किसी भी बहस को कभी सांप्रदायिकता की तरफ सोडें का प्रयत्न करते हैं तो थे, तनाव में आकर एक दूसरे को कागजी राकेट व मिसाइल दिखा कर ऐसे बरस रहे थे गोया अभी एक टम्पे प्रय इर्दीं कागजी करते हैं ताकि इनके शतमाशेश में कोई कमी या कसर न रह जाए। जाहिर है यह बातें वास्तविक वैतिकता की प्रक्रमित के

संबोधनों में कई बार यह कह चुके हैं कि जनता को टी वी देखना बंद कर देना चाहिए। रवीश कुमार स्वयं एन डी टी वी इंडिया जैसे देश के प्रमुख समाचार नेटवर्क में संपादक हैं तथा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध रामनाथ गोयनका पुरस्कार, प्रतिष्ठित गणेशशंकर विद्यार्थी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ सरकार के माधव राव जैसे सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। आज भी वे एनडीटीवी इंडिया के प्रमुख कार्यक्रमों प्राइम टाइम शो व देस की बात जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों को एक एंकर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने 2016 में 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयोंशू की सूची में भी उनका नाम शामिल किया था। सवाल यह है कि टेलीवीजन जगत का इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितारा ही स्वयं क्यों कह रहा है कि लोगों को टी वी वी देखना बंद कर देना चाहिए? यहाँ तक कि वे अपने टी वी चैनल को भी न देखने की

हासिल किया जा सकता है। यहां इस बात को अभी छोड़ देते हैं कि अधिकांश टी वी चौनल्स गोदी मीडिया की भूमिका अदा करते हुए सत्ता की चाटुकारिता करने व सत्ता के एजेंडे को परोसने के साथ साथ सत्ता से सवाल करने के बजाए विषय से ही सवाल करने व विषय को कटघरे में खड़ा करने में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसके अलावा सत्ता के भोंपू बने इन्हीं चौनल्स के अनेक युवा पत्रकारों के किसी भी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने, किसी विषय पर बहस करने -कराने या अपने आमंत्रित अतिथि से सवाल जवाब करने के तौर तरीके उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली उनके तेवर, उनके शारीरिक हावू भाव, उनका गला फड़ अंदाज-ए-बयां आदि को यदि गौर से देखा जाए तो यह तो पता ही नहीं लगता की स्वयं को पत्रकार समझने की गलतफहमियाँ पालने वाले ये ये तत्व गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, कमलेश्वर व धर्मवीर

प्रस्तुतीकरण के अंदाज से साफ़ झलकता है कि इनका एजेंडा किसी विषय पर गंभीर चिंतन करना या उसे तथ्यपूर्ण तरीके से गंभीरता के साथ जनता के सामने पेश करना नहीं बल्कि विषय विशेष का पूर्णतयः व्यावसायिक उपयोग करते हुए उसे और अधिक उलझाना, मुद्दे में विवादित पहलू तलाश कर उसे शीषक या ब्रेकिंग न्यूज बनाना, अपने अतिथियों के साथ बदतमीजी से पेश आते हुए उन्हें भड़काना व उन्हें गुस्से में लाकर उनके मुँह से कुछ ऐसे वाक्य निकलवाना होता है जिससे कोई विवाद खड़ा हो सके। आजकल एंकर की भूमिका निभाने वाले युवक व युवतियां यह भी नहीं देखते कि जिस अतिथि को उन्होंने आमत्रित किया है वे उन एंकर्स से उम्र व अनुभव में कितने बड़े हैं। ये सभी के साथ इस लहजे से बात करते हैं गोया इन्होंने उसे बुलाया ही अपमानित करने के लिए है। जब चाहें ये पूर्वाग्रही एंकर जोकि अपना एजेंडा निर्धारित कर

बाद के स्वयंभू रखवाले इसी भी भारतीय व्यक्ति गठन अथवा दल को राष्ट्रीय राष्ट्रद्वेषी साक्षित करने जिम्मा उठा लेते हैं। के इसी तरह के घटिया स्तरीय प्रस्तुतीकरण का है कि कई बार ऐसे टी प्रेच, धक्का-मुँझी व एक देख लेने की धमकी देने वाले एँ घट चुकी हैं। यहाँ तक कि चप्पल ने, तानने व दिखाने की भी कई बार हो चुकी वी एंकर भी अपने ही से भी गलियां खा चुके हैं दिनों तो एक नव टी वी चौनल के एक वादित संपादक ने महज भी के लिए ऐसा तमाशा आया जो पत्रकारिता के में अब तक का सबसे बाशा कहा जा सकता व पाकिस्तान के दो जो अपने अपने ड्राइंग स्टूडियो से जुड़े हुए हथियारों से हमला कर देंगे। यह इत्तेफ़क हरगिज नहीं हो सकता कि दोनों ही देशों के दोनों ही अतिथि मानसिक रूप से एक साथ एक जैसी तैयारी कर हाथों में मिसाइल व राकेट के खिलोने लेकर एक दूसरे को धमकाने आए हों। शत प्रतिशत यह पूर्व नियोजित व तय शुदा था तथा उन्हें उकसाने के लिए जान बूझकर एंकर द्वारा ऐसे शब्दों व वाक्यों का इस्तेमाल किया जा रहा था की एक दूसरे पर वे कागजी शस्त्र उछल कर उन्हें डराएं धमकाएं। वैसे भी आजकल इन चौनल्स में कार्यक्रमों के जिस तरह के नाम रखे जा रहे हैं और कार्यक्रम के दौरान जिस तरह की लाईट-साउंड-म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है उसे पत्रकारिता के लक्षण नहीं बल्कि नाटक, फिल्म व मनोरंजन का गुण जरूर कहा जा सकता है। राजनैतिक दलों के कुछ प्रवक्ता भी ऐसे हैं जो ऐसे टी वी एंकर्स से वैचारिक समानता रखते हैं उन्हें भी ये एंकर जरूर आमत्रित रसातल में जाने के लक्षण हैं जिसे कोई भी गंभीर व पत्रकारिता के मूल्यों व दायित्वों की कद्र करने वाला व्यक्ति न तो सहन कर सकता है न ही इस वातावरण में स्वयं को इसमें समायोजित कर सकता है। निश्चित रूप से एंजेंडा पत्रकारिता की ही वजह से आज देश बेहद चिंतनीय दौर से गुजर रहा है। जनता को गलत सूचनाएं परोसी जा रही हैं, सही खबरों को छुपाया जा रहा है, किसानों, मजदूरों, छात्रों, गरीबों के हक व अधिकार की बात करने के बजाए सत्ता धीशों की भाषा बोली जा रही है। मंहगाई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती बल्कि चीन पाकिस्तान मंदिर मस्जिद जैसे विषयों पर बहस कराई जाती है। और आपके ड्राइंग रूम में ही बैठे बैठे आपको वैचारिक रूप से गुमराह कर दिया जाता है। तभी खोश कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकार को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि टी वी देखना बंद करने में ही आपकी भलाई है।

क्या कोरोना संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव निर्धारित समय पर नहीं का प्रभाव-प्रसार, खेमे-बंदी को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि से हल करवा देंगे और पांच साल बाद जब अपने ही क्षेत्र में लौटेंगे, तो उनके प्रति स्वाभाविक विश्वास विधानसभा में शहर के तीन बड़े विश्रामघाट हैं। यहां व्यवस्थाओं व सुविधाओं में सुधार की को इंदौर से पानी की जरूरत नहीं है, उसके हिस्से का पानी सांवरे विधानसभा क्षेत्र को दिया जा है। हर बार गर्मी में पानी के लिए झांगड़े होते हैं। अमृत जल योजना के तहत पाइप लाइन भी डाली गई

हा पाएग? प्रदेश म तख्कापलट, मंत्रिमंडल विस्तार और फिर विभाग वितरण के बाद अब यह सवाल बार-बार पूछा और दोहराया जा रहा है। बीते 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायक इस्टीफ देकर भाजपा के हो गए थे। 19 मार्च तक सभी के इस्टीफे मंजूर किए गए। 19 अगस्त तक छह महीने पूरे हो रहे हैं। इस्टीफ देने से रिक्त हुई विधानसभा सीट पर चुनाव छह महीने के अंदर कराना जरूरी होता है। वैसे भी कोरोनाकाल के नए-नए आंकड़े अब नए-नए राजनीतिक समीकरण सामने ला रहे हैं। क्योंकि, मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब 14 मंत्री, विधायक नहीं हैं! शिवराज की टीम में उन्हें मिलाकर 34 मंत्री हैं। इनमें 14 मंत्री पूर्व कांग्रेसी हैं। यहीं वे हैं जो अभी विधायक भी नहीं हैं। सत्ता परिवर्तन के पश्चात प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को, विपक्ष द्वारा राजनीतिक अस्थिरता की उपमा दी गई थी। तर्क यह भी दिया गया कि भाजपा में निर्णय का केंद्राधिकार अब समाप्त हो चुका है। कभी कमल नाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिध्धिया खेमों में विभाजित रही कांग्रेस का यह आरोप भी चौका गया कि भाजपा

कमल नाथ सरकार गणन के पूर्व सिद्धिया की तरफ से अनेक अबोले-अलिखित अनुबंध हो चुके थे। यही बजह है कि सिद्धिया समर्थक विधायक अब मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश की सेवा का संकल्प देहा रहे हैं। दरअसल, समर्थन और समर्थकों की ऐसी सियासत मध्य प्रदेश में पहली बार देखी जा रही है। इसीलिए, बिना किसी संशय के एक सवाल बार-बार पूछा जा रहा है कि अपने-अपने राजनीतिक आकाओं की अनुकंपा से पद, कद और प्रभाव में वृद्धि करने वाले शमाननीय मंत्रीगणश प्रदेश की समस्याओं से कितना सरोकार रख पाएँगे? चुनावी दावों-वादों से दूर अब जन-मन की पीड़ि-परेशानियों से कैसे सीधा सामंजस्य बैठा पाएँगे? वैसे कहा यह भी जाता है कि राजनीति में हितबद्धता ज्यादा मायने नहीं रखती है। यदि व्यक्ति परिणामदायक व्यवस्था नहीं बना पाता है तो राजनीतिक व्यवस्थाएँ कब विवशताओं में बदल जाती हैं, पता नहीं चलता! मत्रियों को जन अपेक्षाओं के ऐसे ही दबाव-समूह की उपस्थिति हमेशा अनुभव करना चाहिए। इस पवित्र उद्देश्य के साथ कि प्रदेश की परिधि काफ़ी बड़ी है, यदि वे अपने विधानसभा क्षेत्र की

स्थाइ रूप से बना रहगा। इसा बहाने इस बात का भी अनुभव हो जाएगा कि प्रदेश की जमीनी समस्याओं पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है? तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और इमरती देवी घोषित रूप से सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और राजनीतिक गलियारों की खुसर-पुसर पर भरोसा करें तो विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह और विजय शाह का नाम शिवराज समर्थकों की प्राथमिकता सूची में दर्ज है। अब इन्हीं मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र से बात आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी समस्याएँ हैं, जो इलाके के लोग लंबे समय से हल करवाना चाहते हैं। कुछ बहुत सामान्य है, कुछ को पूरा होने में वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है। हो सकता है कुछ ऐसी भी हों, जिसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत हो। लेकिन, व्यापक दृष्टिकोण में देखेंगे तो ऐसी छोटी-बड़ी समस्याएँ प्रदेश के हर इलाके में मौजूद हैं। मंत्री चाहें तो अपने इलाके की समस्याओं के जरए एक ऐसा पड़ताल-प्रबंधन विकसित कर सकते हैं, जो प्रदेश स्तर पर उपयोगी और निर्णायक हो सकता है। भोपाल के इस बड़े इलाके में जलभराव की स्थिति बनती है। क्षेत्र में कई बसितियां निचले इलाकों में हैं। पार्किंग की

ता ह। नरला म बीते कई चुनावों में ने के खुर्द में कृषि कार्य संयंत्र बनाने के छोटे-कारखाने चल रहे हैं। जिथे एग्रो मॉल की तरफ आ रही है। इससे सभी को एक छत के नीचे बाजार मिलेगा और पहचान बन सकेगी। जिला बनाने के लिए प्रयास हुए थे। यदि इसे योजना जाता है तो खुर्द के नीचे भी भरपूर फयदा होता है। खंडवा जिले के वर्वास स्थल पर बसे तीन गांवों को भूखंड का नाम हक नहीं मिल पा रहा। अमीन एनवीडीए के नाम द्वारा प्रभावितों को न तो बैंक से कर्ज मिल पा र न ही वे इसे बेच पा र्यटन विकास के लिए पश्चिम कालीभीत के नाम मिलाकर अभयारण्य बन लंबे समय से महसूस ही है। क्योंकि, सागौन जंगल होने के साथ संख्या में वन्य प्राणी भी व्यायाम से जुड़े ग्रामीण में अभी तक नर्मदा नदी लिए पाइप लाइन नहीं बन, नर्मदा लाइन देवास

सकता ह। सावर इलाके में भा रोजगार को लेकर कोई बड़े औद्योगिक क्षेत्र नहीं हैं। बरलाई शुगर मिल की जमीन का उपयोग इसके लिए किया सकता है। सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र के तहत सुरखी, बिलेहरा, राहतगढ़, जैसीनगर मूलतः कृषि आधारित इलाके हैं। सिंचाई के लिए यहां के किसान पुरातन जलस्रोतों पर अधिक आश्रित हैं। सुरखी और रायसेन जिले की सीमा पर तीन साल पहले बेबस सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस पर अब शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। जल संसाधन विभाग ने बेबस सिंचाई परियोजना का पूरा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था, सर्वे भी हो चुका था, लेकिन अनुमति नहीं मिल सकी। यह परियोजना स्वीकृत होने से सागर की पेयजल परियोजना को भी फयदा मिल सकता है। ग्वालियर जिले के डबरा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इलाके की ढाई लाख आबादी के लिए बनाया गया सिविल अस्पताल सिर्फनाम का है। करीब साढ़े छह करोड़ रुपये मंजूर भी हुए हैं। यह कार्य पूरा होने से एक बड़ी आबादी को काफी मदद मिलेगी। डबरा शहर के आधे

हा। गुणवत्ता का स्तर बहतर नहीं होने से वह कभी भी टूट जाती है। नई पाइप लाइन का खर्च करीब 40 लाख रुपये बताया जा रहा है।

छह विधानसभा क्षेत्रों से चुनकर आते रहे, छह मंत्रियों से जुड़ी ये समस्याएं प्रमाण हैं कि बड़े नेताओं के इलाकों में भी छोटी-छोटी समस्याएं आम हैं। समस्याओं का यह विवरण भी आम आदमी द्वारा आमतौर पर दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं से ही लिया गया है। यदि इन परेशनियों को हम शेष प्रदेश की समस्याओं के साथ खें, तो बहुत-सी ऐसी समानताएं साफ़दिखाई देंगी, जो एक-एक करके बहुत बड़ी हो जाती हैं। मंत्रियों को परखने का एक पैमाना यह भी हो सकता है कि यदि वे अपने इलाके की समस्याओं को हल करवा पाते हैं, तो वहां से मिले अनुभवों के आधार पर प्रदेश की बाकी परेशनियों का निराकरण भी कर सकते हैं। स्वाभाविक है अपने ही मतदाताओं का विश्वास अर्जित करें और प्रदेश के बड़े इलाके में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाएं। फिलहाल तो उम्मीद ही की जा सकती है कि राजनीतिक समायोजन की शह-मात में उभर कर आए ये नुमाइदे, कुछ तो ऐसा जरूर करेंगे कि अपने क्षेत्र और

